



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938

No. 676]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 751(अ).—जबकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान हेतु एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी प्रदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को उनकी हकदारियां सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सीधे प्राप्त करने के समर्थ बनाता है तथा आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विविध दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

तथा कि, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय का राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से नकदी और गैर-नकदी संघटक देकर बंधित श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बंधित श्रमिक पुनर्वास स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

तथा बंधित श्रमिक पुनर्वास स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह उसके पास आधार संख्यांक के होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार ऐसे सभी हकदार फायदाग्राहियों, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं है या, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक हैं, अपेक्षित है कि वे 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें परंतु वे उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार प्राप्त करने के हकदार हों तथा

ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यू आई डीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनसीएलपी सोसायटी कहा गया है) के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करें और यदि उनके ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना सोसायटी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्यवय से या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में के संबंधित विभाग यूआईडीएआई का रजिस्ट्रार बनकर या एनसीएलपी सोसायटी को नामांकन अभिकरण; के रूप में लगाकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

परन्तु स्कीम के व्यक्तियों का आधार नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या

(ii) नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रतिलिपि; तथा

(घ) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iii) पासपोर्ट या मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) सरकारी पत्र-शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र जारी फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र; या (vi) राशन-कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजनार्थ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन सुविधाजनक और बाधरहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाएं देकर तथा अन्य माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों पर जाकर 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सकेगी तथा उन्हें स्थानीय नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राहियों लाभार्थी ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे आस-पास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों में इस स्कीम के क्रियान्वयन को भारसाधक विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा है तथा अपने जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के पास या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से फायदाग्राहियों से, अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा (1) के उप-पैरा (3) के परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर कराने हेतु अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय तथा जम्मू - कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. जी-20021/01/2016-बीएल]

हीरा लाल सामरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi; the 6th March, 2017

S.O. 751(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Labour and Employment, in the Government of India, is administering the Bonded Labour Rehabilitation Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for rehabilitation of bonded labourer by giving Cash and Non-cash component through the National Child Labour Project Society in the State Government or Union Territory Administration;

And whereas, the Benefits under Bonded Labour Rehabilitation Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016(18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme hereby, is required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) All such eligible beneficiaries entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar Number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI's website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through the National Child Labour Project Society (hereinafter referred to as NCLP Society) which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through the National Child Labour Project Society may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations by becoming UIDAI Registrar or engaging NCLP Society as enrolment agency:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individuals of the Scheme, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:—

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Ration Card; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme, the Ministry of Labour and Employment through National Child Labour Project Society shall make all the required arrangements including the following; namely:-

- (1) Wide publicity through media and individual notices through the district National Child Labour Project Society and other means, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.
- (2) In case, beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the block or Tehsil or Taluka, the Department in charge of implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph (1) with their District National Child Labour Project Society or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. G-20021/01/2016-BL]

HEERA LAL SAMARIYA, Addl. Secy.